ऊर्जा क्षेत्र को दिया 61071 करोड़ का बजट

# वैकल्पिक व हरित ऊर्जा को बढ़ावा, बनी रहेगी बिजली की चमक

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने बजट में ऊर्जा सेक्टर की परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 61071 करोड़ के बजट प्रावधान किया है। प्रदेश में अप्रैल से सितंबर 2025 (छह माह) के बीच भीषण गर्मी में प्रदेशवासियों को शाम से सुबह तक निरंतर बिजली देने के लिए 3000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। वहीं वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में हरित ऊर्जा पर फोकस बढ़ाया है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा के साथ ही पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के लिए 3953 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें एनटीपीसी के सहयोग से 200 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी।

- प्रदेश में पांच वर्ष में 22 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी भवनों और पार्कों को भी सोलर आधारित बना दिया गया है। अब अन्य 16 नगर निगमों को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। कंप्रेस्ड बायो गैस, बायो कोल और बायो डीजल की की 53 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिसमें 24 स्थापित हैं। ब्यूरो

### बजट में ये भी

- 456 करोड़ रुपये आरडीएसएस के दिए गए हैं बिजली व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए
- 100 करोड़ से 7000 विद्यालयों के ऊपर से गुजर रहे बिजली के हाईटेंशन तारों को हटाया जाएगा
- 12000 करोड़ पावर कार्पोरेशन को क्षतिपूर्ति अनुदान के लिए
- 2700 करोड़ से राजस्व क्षतिपूर्ति के तहत विद्युत करों को होगा भुगतान
- 18000 करोड़ रुपये निजी नलकूपों के अनुदान के लिए मिला

# कानपुर और आगरा में बनेंगे लेदर फुटवियर पार्क

## प्रदेश सरकार देगी 300-300 एकड़ जमीन, 12 फीसदी सालाना की दर से बढ़ रहा फुटवियर सेक्टर

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। बजट में सरकार ने कानपुर और आगरा में दो लेदर फुटवियर पार्क की सौगात दी है। इसके लिए सरकार 300-300 एकड़ जमीन देगी। बजट में दोनों पार्कों के विकसित करने के लिए 20 लाख रुपये के टोकन मनी की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि लेदर पार्क का प्रावधान केंद्र सरकार के बजट में किया गया था।

प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने बताया कि फुटवियर सेक्टर में खासी संभावनाएं हैं। ये बाजार 12 फीसदी सालाना की दर से बढ़ रहा है। यही वजह है कि दोनों लेदर पार्क में फुटवियर की इकाइयों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। इसमें लेदर के साथ-साथ नॉन लेदर फुटवियर इकाइयों की भी स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 6000 करोड़ का पैकेज देने का एलान किया था। कानपुर, उन्नाव, आगरा और नोएडा इंडस्ट्री के प्रमुख नोड हैं। इनके जरिए 2030 तक सालाना चार हजार करोड़ रुपये की ग्रोथ का अनुमान है।

चर्म निर्यात परिषद के चेयरमैन आरके जालान ने बताया कि इन पार्कों से महिलाओं को प्रशिक्षित व सहभागी बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। सीएम योगी के विजन के अनुरूप यूपी में नए लेदर पार्क बनेंगे, जहां टेनरियां नहीं बल्कि उत्पाद तैयार होंगे। लेदर के नए क्लस्टर विकसित होंगे, जिनसे नए जिलों को लाभ मिलेगा। चर्म निर्यात परिषद के पूर्व चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने सीएम योगी को धन्यवाद देते हुए कहा कि लेदर और नॉन लेदर को एक ही श्रेणी में रखने से फुटवियर और एक्सेसरीज इंडस्ट्री में तेजी आएगी।

# उद्यमियों को दुनियाभर में ट्रेड शो के लिए सरकार देगी पैसा

**लखनऊ।** प्रदेश के उद्यमियों को ग्लोबल प्लेटफार्म पर स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार मदद करेगी। उनकी ब्रांडिंग से लेकर मार्केटिंग तक में सहयोग के लिए बजट में अलग-अलग प्रावधान किया गया है। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के छोटे उद्यमियों के उत्पादों को दुनिया के सामने न केवल लाना है बल्कि पहुंचाना भी है। इसके लिए बजट में 63 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

### 63 करोड़ रुपये का किया गया प्रावधान अलग-अलग मदों में

यूपी में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेशों में होने वाले रोड शो और सेमिनार में यूपी के उद्यमी भी हिस्सा लेंगे। इस मद में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो में हिस्सा लेने के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रेटर नोएडा में इस वर्ष होने वाली मोटो जीपी रेस के लिए भी 20 करोड़ रुपये बजट में दिए गए हैं। ब्यूरो

# इलेक्ट्रिक बसों, चार्जिंग स्टेशनों के लिए मिले 450 करोड़ रुपये

अमर उजाला ब्यूरो

**लखनऊ।** प्रदेश सरकार यातायात को सुगम बनाने के लिए परिवहन विभाग पर 550 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बजट में मिले इस पैसे से रोडवेज के बेड़े में 400 नई ई बसें जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इनके लिए चार्जिंग स्टेशनों का भी विकास किया जाएगा।

बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान रोड़वेज के बेड़े में 400 नई ई बसों को जोड़ने के लिए किया गया है। इन बसों से शहरों को जोड़ा जाएगा। इससे पहले 120 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का रास्ता साफ हो चुका है। इसमें 20 डबलडेकर बसें भी शामिल रहेंगी। वहीं गांवों तक हाईटेक बसों की सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के तहत 100 करोड़ रुपये मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए

### रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 400 ई बसें, 50 करोड़ से बनेंगे चार्जिंग स्टेशन

दिए गए हैं। मध्यम श्रेणी की ई बसों में 40-42 सीटें होती हैं, जिन्हें छोटे रूटों पर आसानी से चलाया जा सकेगा। यह बसें एक चार्ज होने पर पर 200 किमी तक चलती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है।

# बेहतर सड़कों से रफ्तार पकड़ेंगे उद्योग धंधे

डॉ. एमपी सिंह
अर्थशास्त्री, निदेशक, एमपीजीआई ग्रुप

विशेषज्ञ की राय

लघु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन पर ज्यादा जोर

प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 में आर्थिक विकास मॉडल पर खास ध्यान दिया है। इसमें आधारभूत संरचना, सूक्ष्म, लघु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन पर ज्यादा जोर दिया गया है। बजट को समग्रता से देखें तो ये दूरगामी है, जिसके अप्रत्याशित परिणाम दो साल में ही दिखने लगेंगे। जिस राज्य का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, वही सिकंदर होगा। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसका उदाहरण हैं।

प्रदेश सरकार ने सड़क, पुल, बाईपास, रिंग रोड और एक्सप्रेसवे को सबसे ज्यादा बजट दिया है। इसके जरिये उद्योगों पर फोकस किया गया है ताकि छोटे जिलों और कस्बों में भी उद्योग लगाए जा सकें। मेडिकल क्षेत्र में सीटें बढ़ाने और सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जारी आयुष्मान भारत के भुगतान, गन्ना किसानों के भुगतान, पर्यटन क्षेत्र के विस्तार, परिवहन सेवा में वृद्धि को ध्यान में रखकर बजटीय प्रावधान किए गए हैं। कुल मिलाकर प्रदेश का बजट आर्थिक विकास को गति देने वाला कहा जा सकता है।

### महिला सम्मान व विकास पर दिया है जोर

गन्ना किसानों के साथ कृषि विस्तार के लिए जैविक खेती, सिंचाई, बीज आदि के लिए बजट में प्रावधान किया है। महिला सम्मान व विकास पर जोर दिया है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 1500 सीटें सरकारी और 3000 सीटें निजी कॉलेजों की बढ़ाई गई हैं, जो सराहनीय है।

## और रफ्तार पकड़ेगा बुंदेलखंड

- बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित जिलों के पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से 425 करोड़ की व्यवस्था
- 50 करोड़ रुपये से चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का होगा विकास

- जालौन में 500 मेगावट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 150 करोड़, गरौठा (झांसी) में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के मिले 80 करोड़

### पूर्वांचल विकास निधि के तहत मिले 125 करोड़

- बजट में क्षेत्रीय विकास निधि (पूर्वांचल) के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह राशि मुख्य रूप से छोटी सड़कों के निर्माण पर खर्च होगी।